

प्रेषक,

राम सिंह,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री सन्दीप कुमार,  
अधिवक्ता,  
मकान नं०-432/38 सिविल लाईन्स,  
जादूगर रोड, रुड़की, हरिद्वार।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 23 मई, 2016

विषय : मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु  
स्थायी अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको स्थायी अधिवक्ता के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

2- आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-136/XXXVI(1)/2016-43-एक (1)/03 दिनांक 10.03.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि सहमत हो तो कृपया अपनी लिखित सहमति उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या-266 /XXXVI(1)/2016-266/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमशः.....2